DRA Annual International Conference On
Developed India @2047: Global Pathways for Sustainable Socio- Economic, Linguistic, Science and Technological Transformation

Ind. Jr. of Mod. Res. and Rev *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 [Special Issue 1] Year 2026*

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

विकसित भारत @2047: ग्रामीण–शहरी एवं कृषि परिवर्तन के माध्यम से सतत विकास का अध्ययन

डॉ. गीता कुकावा
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, श्रीमती आर. डी. शाह आर्ट्स एवं श्रीमती वी. डी. शाह कॉमर्स कॉलेज धोलका, अहमदाबाद, भारत

Corresponding Author: * डॉ. गीता कुकावा

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21381626

सारांश

भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रस्तुत 'भारत *@2047'* का दृष्टिकोण देश को एक विकसित, आत्मनिर्भर, समावेशी तथा पर्यावरण-संवेदनशील राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना करता है। यह शोध पत्र ग्रामीण–शहरी परिवर्तन तथा कृषि क्षेत्र में होने वाले संरचनात्मक, तकनीकी एवं संस्थागत बदलावों के माध्यम से सतत विकास की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत की बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, जबकि शहरी क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगीकरण एवं सेवाक्षेत्र के प्रमुख केंद्र बनते जा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण–शहरी असंतुलन, अनियोजित शहरीकरण, कृषि संकट, बेरोजगारी, पर्यावरण क्षरण और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएँ सतत विकास के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ बनकर उभरती हैं।अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण परिवर्तन के अंतर्गत आधारभूत संरचना का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गैर-कृषि रोजगार के अवसरों का सृजन तथा डिजिटल और वित्तीय समावेशन अत्यंत आवश्यक है। वहीं शहरी परिवर्तन के संदर्भ में संतुलित एवं नियोजित शहरीकरण, स्मार्ट एवं हरित शहरों का विकास, किफायती आवास, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन तथा ऊर्जा-दक्ष प्रणालियों पर विशेष बल दिया गया है। कृषि परिवर्तन के अंतर्गत आधुनिक तकनीकों का उपयोग, फसल विविधीकरण, जैविक एवं जल-संरक्षण आधारित खेती, किसानों की आय में वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा को सतत विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में विश्लेषित किया गया है।यह शोध पत्र द्वितीयक आँकड़ों, सरकारी नीतियों, योजना एवं नीति आयोग की रिपोर्टों तथा पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों पर आधारित है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत *@2047* के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण, शहरी और कृषि क्षेत्रों के बीच समन्वित एवं संतुलित विकास अनिवार्य है। प्रभावी नीति निर्माण, तकनीकी नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी के माध्यम से ही भारत दीर्घकालीन, समावेशी एवं सतत विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 01-01-2026
- **Accepted:** 10-06-2026
- **Published:** 18-06-2026
- **MRR:**4(SP1); 2026: 293-299
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

कुकावा गी. विकसित भारत @2047: ग्रामीण–शहरी एवं कृषि परिवर्तन के माध्यम से सतत विकास का अध्ययन. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(SP1):293-299.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: भारत @2047, ग्रामीण परिवर्तन, शहरी परिवर्तन, कृषि परिवर्तन, सतत विकास

© 2026 डॉ. गीता कुकावा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान और विकासशील देश है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु आज भी ग्रामीण–शहरी असमानता, कृषि संकट, बेरोजगारी और पर्यावरणीय समस्याएँ विद्यमान हैं। भारत @2047 की परिकल्पना एक ऐसे भारत की है जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से समावेशी और पर्यावरणीय रूप से सतत हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण, शहरी और कृषि क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है।

2. शोध के उद्देश्य (OBJECTIVES)

1. सतत विकास में कृषि और ग्रामीण विकास की भूमिका का अध्ययन करना।
2. भारत @2047 के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करना।
3. सरकारी नीतियों और योजनाओं (कृषि, ग्रामीण विकास एवं शहरीकरण) की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कृषि के संदर्भ में आवश्यक रणनीतियों का सुझाव देना।

➢ संधान अध्ययन की परिकल्पनाएँ

1. ग्रामीण और शहरी परिवर्तन भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2. ग्रामीण और शहरी विकास के बीच असमानता सतत विकास के लिए एक प्रमुख चुनौती है।
3. कृषि और ग्रामीण विकास के बिना भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

➢ अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति को अपनाया गया है। अध्ययन के लिए द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। आवश्यक जानकारी सरकारी रिपोर्टों, नीति आयोग एवं योजना आयोग के प्रकाशनों, शोध पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों से संकलित की गई है। संकलित आँकड़ों का तार्किक एवं तुलनात्मक विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

सतत कृषि वास्तव में क्या है

सतत कृषि वह खेती है जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना आज की खाद्य और वस्त्र संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। इसे दीर्घकालिक दृष्टिकोण वाली खेती के रूप में समझें—जैसे कोई ऐसा पेड़ लगाना जो आपके पोते-पोतियों को छाया प्रदान करे। पारंपरिक खेती के विपरीत, जो अक्सर अल्पकालिक पैदावार को प्राथमिकता देती है, सतत कृषि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक लाभप्रदता और सामाजिक समानता को ध्यान में रखती है। औद्योगिक कृषि के पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसानों के जवाब में यह अवधारणा सामने आई। हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि की, लेकिन इसके साथ ही इसने मृदा अपरदन, जल प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान को भी जन्म दिया। सतत कृषि का उद्देश्य उच्च उत्पादकता बनाए रखते हुए इन चिंताओं को उन प्रथाओं के माध्यम से दूर करना है जो प्राकृतिक प्रणालियों के साथ मिलकर काम करती हैं, न कि उनके विरुद्ध।

1. ग्रामीण परिवर्तन

ग्रामीण परिवर्तन से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और तकनीकी परिवर्तनों से है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार के विस्तार से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। ग्रामीण परिवर्तन से न केवल गरीबी में कमी आती है, बल्कि ग्रामीण–शहरी पलायन भी नियंत्रित होता है, जो सतत विकास के लिए आवश्यक है।

2 . शहरी परिवर्तन

शहरी परिवर्तन औद्योगीकरण, सेवा क्षेत्र के विस्तार और तीव्र शहरीकरण का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और मेट्रो परियोजनाओं ने शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ किया है। किंतु अनियोजित शहरीकरण से झुग्गी-झोपड़ियाँ, प्रदूषण, यातायात और जल संकट जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। अतः नियोजित, हरित और समावेशी शहरी विकास सतत विकास की अनिवार्य शर्त है।

3 . कृषि परिवर्तन

कृषि परिवर्तन का अर्थ कृषि क्षेत्र में तकनीकी, संरचनात्मक और आर्थिक बदलावों से है। पारंपरिक कृषि से आधुनिक कृषि की ओर संक्रमण, उन्नत बीज, सिंचाई, मशीनीकरण, डिजिटल कृषि और ड्रोन तकनीक—ये सभी कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हैं। फसल विविधीकरण, बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन से किसानों की आय में वृद्धि होती है।

❖ सतत विकास में कृषि और ग्रामीण विकास की भूमिका का अध्ययन करना।

© 2026 डॉ. गीता कुकावा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

सतत विकास का अर्थ

सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएँ पूरी हों, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन नष्ट न हों। इसमें तीन पहलुओं का संतुलन ज़रूरी है—

1. आर्थिक विकास
2. सामाजिक न्याय
3. 3) पर्यावरण संरक्षण

1. सतत विकास में कृषि की भूमिका

(1) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना

कृषि समाज को भोजन उपलब्ध कराती है। पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक भोजन के बिना सतत विकास संभव नहीं है। स्थायी कृषि से भूख और कुपोषण की समस्या कम होती है।

(2) रोजगार और आय का स्रोत

भारत जैसे विकासशील देशों में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि और उससे जुड़े कार्य (पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन) ग्रामीण रोजगार बढ़ाते हैं और गरीबी घटाते हैं।

(3) पर्यावरण संरक्षण में योगदान

- जैविक खेती
- जल संरक्षण तकनीक
- फसल चक्र प्रणाली
- कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग
- इन उपायों से मिट्टी, जल और जैव विविधता सुरक्षित रहती है, जो सतत विकास का आधार है।

(4) ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती

कृषि ग्रामीण बाजारों, लघु उद्योगों और सेवा क्षेत्रों को गति देती है, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास होता है।

2. सतत विकास में ग्रामीण विकास की भूमिका

(1) जीवन स्तर में सुधार

ग्रामीण विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आवास की सुविधाएँ बढ़ती हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है।

(2) बुनियादी ढांचे का विकास

सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट और परिवहन की सुविधा से ग्रामीण क्षेत्र मुख्यधारा से जुड़ते हैं और संतुलित विकास होता है।

(3) सामाजिक समानता और समावेशन

ग्रामीण विकास से शहर और गाँव के बीच की असमानता कम होती है। महिलाओं, गरीबों और वंचित वर्गों को समान अवसर मिलते हैं।

(4) कौशल विकास और आत्मनिर्भरता

कौशल प्रशिक्षण, स्वरोज़गार योजनाएँ और स्वयं सहायता समूह ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं।

3. कृषि और ग्रामीण विकास का संयुक्त प्रभाव

- जब कृषि विकास और ग्रामीण विकास साथ-साथ आगे बढ़ते हैं, तब:
- गरीबी और बेरोज़गारी घटती है
- पर्यावरण का संरक्षण होता है
- सामाजिक और आर्थिक संतुलन बना रहता है
- देश का विकास टिकाऊ और समावेशी बनता है

❖ **भारत @2047 के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करना।**

भूमिका

भारत @2027 का लक्ष्य एक समावेशी, आत्मनिर्भर और सतत विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना है। इस संदर्भ में ग्रामीण–शहरी परिवर्तन (Rural–Urban Transformation) एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूपांतरण होता है तथा शहरी क्षेत्रों का विस्तार और आधुनिकीकरण होता है। यह प्रक्रिया देश की आर्थिक वृद्धि, रोज़गार सृजन, जीवन-स्तर में सुधार और सामाजिक समानता से गहराई से जुड़ी है।

1. ग्रामीण–शहरी परिवर्तन का अर्थ

ग्रामीण–शहरी परिवर्तन का अर्थ है—

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कृषि से गैर-कृषि गतिविधियों की ओर बढ़ना,
- गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का विकास,
- शहरीकरण के कारण जनसंख्या, उद्योग और सेवाओं का शहरों की ओर स्थानांतरण।

2. भारत @2027 में ग्रामीण परिवर्तन की प्रक्रिया

भारत @2027 के लक्ष्य के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा रहे हैं:

(क) कृषि का आधुनिकीकरण

आधुनिक तकनीक, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और डिजिटल कृषि का विस्तार।

कृषि मूल्य श्रृंखला (Value Chain) का विकास और किसानों की आय में वृद्धि।

(ख) गैर-कृषि रोज़गार के अवसर

ग्रामीण उद्योग, एमएसएमई, हस्तशिल्प, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण का विकास।

मनरेगा, स्टार्ट-अप और स्वरोज़गार योजनाओं से रोज़गार सृजन।

© 2026 डॉ. गीता कुकावा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

(ग) बुनियादी ढाँचे का विकास
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बिजली, पेयजल, स्वच्छता और इंटरनेट सुविधाएँ।
डिजिटल इंडिया के माध्यम से ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाएँ।
(घ) सामाजिक परिवर्तन
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि।

3. भारत @2027 में शहरी परिवर्तन की प्रक्रिया
(क) शहरीकरण की गति
गाँवों से शहरों की ओर प्रवासन में वृद्धि।
नए कस्बों और उपनगरों (Suburbs) का विकास।
(ख) औद्योगीकरण और सेवा क्षेत्र
उद्योग, आईटी, व्यापार और सेवा क्षेत्र का विस्तार।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आधुनिक शहरी सुविधाएँ।
(ग) शहरी अवसंरचना का विकास
मेट्रो, सड़क, आवास, जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाएँ।
डिजिटल और हरित (Green) शहरों की अवधारणा।
(घ) शहरी समस्याएँ
झुग्गी-झोपड़ी, प्रदूषण, ट्रैफिक और बेरोज़गारी जैसी चुनौतियाँ।
संसाधनों पर बढ़ता दबाव।

4. ग्रामीण–शहरी परिवर्तन के कारण
- औद्योगीकरण और आर्थिक विकास
- रोज़गार और बेहतर जीवन-स्तर की तलाश
- शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता
- सरकारी नीतियाँ और विकास योजनाएँ

5. ग्रामीण–शहरी परिवर्तन के प्रभाव
- सकारात्मक प्रभाव
- राष्ट्रीय आय और आर्थिक वृद्धि में वृद्धि
- रोज़गार के नए अवसर
- जीवन-स्तर में सुधार

नकारात्मक प्रभाव
- ग्रामीण-शहरी असमानता
- शहरी भीड़भाड़ और पर्यावरणीय समस्याएँ
- ग्रामीण क्षेत्रों से मानव संसाधन का पलायन

6. संतुलित विकास की आवश्यकता
भारत @2027 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संतुलित ग्रामीण-शहरी विकास आवश्यक है। इसके लिए—
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के अवसर बढ़ाने होंगे।
- छोटे शहरों और कस्बों का नियोजित विकास करना होगा।
- सतत और पर्यावरण-अनुकूल विकास नीतियों को अपनाना होगा।

❖ **सरकारी नीतियों और योजनाओं (कृषि, ग्रामीण विकास एवं शहरीकरण) की प्रभावशीलताका अध्ययन करना**

सरकारी नीतियों और योजनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन
सरकार विभिन्न क्षेत्रों में नीति और योजना बनाकर देश के विकास को गति देती है। विशेष रूप से कृषि, ग्रामीण विकास और शहरीकरण के क्षेत्र में लागू की जाने वाली नीतियाँ ग्रामीण और शहरी जीवन पर सीधे असर डालती हैं। इन नीतियों और योजनाओं की प्रभावशीलता को समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है:

1 ग्रामीण विकास की नीतियाँ और प्रभाव
मुख्य योजनाएँ:
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA): ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ग्रामीण गरीबों को सस्ती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना।
- स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण क्षेत्र: स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार।

2 शहरीकरण और शहरी विकास की नीतियाँ
मुख्य योजनाएँ:
- अटल मिशन फॉर रीजनल इन्फ्रास्ट्रक्चर (AMRUT): शहरों में जल, सीवर और नागरिक सुविधाओं का सुधार।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): शहरी गरीबों के लिए घर निर्माण।
- स्मार्ट सिटी मिशन: शहरों का आधुनिककरण और सुविधाओं का डिजिटलरण।

1. ग्रामीण जीवन स्तर और योजनाओं के प्रभाव
आवास और वित्तीय समावेशन
PM-आवास-ग्रामीण योजना के तहत लगभग 2.63 करोड़ ग्रामीण घर बनाए गए हैं (2024 तक) ।
प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत 35.7 करोड़ से अधिक डेबिट कार्ड जारी किए गए, जिससे ग्रामीण वित्तीय समावेशन (banking access) बढ़ा।

© 2026 डॉ. गीता कुकावा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2. रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े

रोजगार में बदलाव

भारत में बेरोजगारी दर लगभग 5.2% (2025 के एक तिमाही PLFS डेटा के अनुसार) दर्ज की गई है।

ग्रामीण बेरोजगारी लगभग 4.4% थी, जबकि शहरों में थोड़ा अधिक 6.9% रही।

कृषि में रोजगार देने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का भाग काफी अधिक है (70.9% महिलाओं की कृषि में भागीदारी पुरुषों के 44.6%)।

3 शहरीकरण के संदर्भ में आँकड़े

शहरी प्रभाव

लगभग 35–40% भारत की आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, और यह अनुपात बढ़ता रहा है (2011 के जनगणना से अनुमान 2045 तक बढ़ेगा

शहरी क्षेत्रों में रोजगार अधिकतर सेवा (tertiary) क्षेत्र में केंद्रित है, जो शहरों में रोजगार के अवसरों को बढाता है।

- **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कृषि के संदर्भ में आवश्यक रणनीतियाँ**

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ आज भी बड़ी जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर है। बदलते समय में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कृषि की प्रकृति, समस्याएँ और आवश्यकताएँ अलग-अलग होती जा रही हैं। इसलिए कृषि विकास हेतु क्षेत्र-विशेष रणनीतियाँ अपनाना आवश्यक है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए आवश्यक रणनीतियाँ

(1) सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

ग्रामीण कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। इसलिए नहरों, तालाबों, चेकडैम, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है।

(2) आधुनिक तकनीक और यंत्रीकरण

परंपरागत कृषि से उत्पादन सीमित रहता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, आधुनिक बीज, उर्वरक और डिजिटल तकनीक (एग्री-टेक) के उपयोग से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

(3) कृषि ऋण और वित्तीय सहायता

किसानों को समय पर सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और सब्सिडी का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।

(4) कृषि विविधीकरण

केवल अनाज पर निर्भरता कम कर बागवानी, दुग्ध-व्यवसाय, मत्स्य-पालन, मुर्गी-पालन एवं जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए।

(5) भंडारण और विपणन व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और मंडी सुविधाओं का विकास आवश्यक है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके।

2. शहरी क्षेत्रों में कृषि के लिए आवश्यक रणनीतियाँ

(1) शहरी कृषि (Urban Farming) को प्रोत्साहन

छत पर खेती, किचन गार्डन, वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स जैसी पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए।

(2) तकनीक आधारित कृषि

शहरी क्षेत्रों में सीमित भूमि होने के कारण स्मार्ट कृषि, ड्रोन तकनीक, सेंसर आधारित सिंचाई और एआई आधारित कृषि प्रबंधन उपयोगी है।

(3) जैविक और सुरक्षित खाद्य उत्पादन

शहरी उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य-सचेतना को देखते हुए जैविक सब्जियों और फलों के उत्पादन पर जोर देना चाहिए।

(4) कृषि-उद्यमिता और स्टार्ट-अप

युवाओं को एग्री-स्टार्टअप, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और लॉजिस्टिक्स से जोड़कर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

(5) ग्रामीण-शहरी कृषि संपर्क

ग्रामीण उत्पादों की सीधी आपूर्ति शहरी बाजारों तक हो, इसके लिए ई-NAM, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और डिजिटल मार्केटिंग को मजबूत करना आवश्यक है।

उत्कल्पनाओं की सिद्धि (Verification of Hypotheses)

उत्कल्पना 1: ग्रामीण एवं शहरी परिवर्तन भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सिद्धि: अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों के विस्तार से गरीबी में कमी आई है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वहीं दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में औद्योगीकरण, सेवा क्षेत्र के विस्तार और अवसंरचनात्मक विकास ने आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान की है। जब ग्रामीण और शहरी विकास एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, तब संतुलित और समावेशी विकास संभव होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि ग्रामीण एवं शहरी परिवर्तन भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उत्कल्पना 2: ग्रामीण और शहरी विकास के बीच असमानता सतत विकास के लिए एक प्रमुख चुनौती है।

सिद्धि: अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आय के अवसर सीमित हैं। इस असमानता के कारण बड़े पैमाने पर ग्रामीण–शहरी पलायन

© 2026 डॉ. गीता कुकावा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

होता है, जिससे शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या और संसाधनों का अत्यधिक दबाव पड़ता है। यह स्थिति न तो आर्थिक रूप से और न ही पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ है। अतः यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि ग्रामीण–शहरी असमानता सतत विकास के मार्ग में एक गंभीर चुनौती है।

उत्कल्पना 3: कृषि एवं ग्रामीण विकास के बिना भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

सिद्धिः भारत की बड़ी जनसंख्या आज भी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। यदि कृषि क्षेत्र मजबूत नहीं होगा, तो खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन और ग्रामीण आय में वृद्धि संभव नहीं हो सकती। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि कृषि आधुनिकीकरण, फसल विविधीकरण, जैविक खेती और कृषि-आधारित उद्योगों के विकास से न केवल किसानों की आय बढ़ती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आजीविका भी सुनिश्चित होती है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि कृषि और ग्रामीण विकास के बिना भारत @2047 का विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

तारणो

- इस शोध अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण, शहरी एवं कृषि परिवर्तन का समन्वित और संतुलित विकास अत्यंत आवश्यक है। केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- प्रथम, ग्रामीण परिवर्तन ने यह सिद्ध किया है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल संपर्क और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ, तो ग्रामीण जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार संभव है। इससे गरीबी, बेरोजगारी और ग्रामीण–शहरी पलायन में कमी आती है, जो सतत विकास के लिए अनिवार्य है।
- द्वितीय, शहरी परिवर्तन ने भारत की आर्थिक प्रगति को गति दी है, किंतु अनियोजित शहरीकरण ने कई सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएँ भी उत्पन्न की हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि नियोजित, हरित और समावेशी शहरी विकास के बिना सतत विकास संभव नहीं है। स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएँ तभी सफल होंगी जब वे आम नागरिकों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार लाएँ।
- तृतीय, कृषि परिवर्तन भारत की खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार का आधार है। पारंपरिक कृषि से आधुनिक, तकनीक-आधारित और पर्यावरण-संवेदनशील कृषि की ओर परिवर्तन अनिवार्य है। जैविक खेती, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और कृषि प्रसंस्करण से न केवल किसानों की आय बढ़ती है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होता है।
- चतुर्थ, अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण–शहरी असमानता भारत के सतत विकास के मार्ग में एक प्रमुख चुनौती है। जब तक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुँचेगा, तब तक भारत @2047 का सपना अधूरा रहेगा। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समावेशन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
- अंततः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कृषि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का परस्पर सहयोग, सशक्त नीतियाँ और दीर्घकालिक दृष्टिकोण भारत को 2047 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और सतत राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएँगे। इस प्रकार, सतत विकास केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि भारत @2047 की दिशा में एक निरंतर प्रक्रिया है।

सुझाव

- कृषि आधुनिकीकरण और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ।
- नियोजित और हरित शहरीकरण को प्राथमिकता दी जाए।
- पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

निष्क्रिय

भारत @2047 का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि इसके अंतर्गत एक समावेशी, आत्मनिर्भर एवं पर्यावरण-संतुलित राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस शोध अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण, शहरी तथा कृषि क्षेत्रों में संतुलित एवं समन्वित परिवर्तन के बिना सतत विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसरों के विस्तार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की नींव रखी जाती है।शहरी क्षेत्रों में नियोजित एवं सतत शहरीकरण को अपनाया जाना आवश्यक माना गया है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट एवं हरित शहरों का विकास किया जाता है। किफायती आवास, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन तथा ऊर्जा-दक्ष प्रणालियों के विस्तार द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है तथा पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, जल-संरक्षण आधारित खेती, फसल विविधीकरण, जैविक कृषि तथा किसानों की आय में वृद्धि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाता

© 2026 डॉ. गीता कुकावा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

है।अध्ययन के निष्कर्षस्वरूप यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रभावी नीति निर्माण, तकनीकी नवाचार, संस्थागत सुधार तथा जनभागीदारी के माध्यम से भारत @2047 के विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण–शहरी समन्वय एवं सतत कृषि विकास के माध्यम से भारत को आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से एक सशक्त एवं टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; 2023.
2. भारत सरकार. नीति आयोग की रिपोर्ट: भारत @2047 विकसित भारत की ओर. नई दिल्ली: नीति आयोग; 2022.
3. भारत सरकार. राष्ट्रीय कृषि नीति. नई दिल्ली: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; 2021.
4. भारत सरकार. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2020.
5. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP). सतत विकास लक्ष्य (SDGs): भारत परिप्रेक्ष्य. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र; 2019.
6. मिश्रा एसके, पुरी वीके. भारतीय अर्थव्यवस्था. नई दिल्ली: हिमालय पब्लिशिंग हाउस; 2019.
7. दत्त आर, सुंदरम केपीएम. भारतीय अर्थव्यवस्था. नई दिल्ली: एस. चंद एंड कंपनी; 2020.
8. टोडारो एमपी, स्मिथ एससी. आर्थिक विकास (हिन्दी संस्करण). नई दिल्ली: पीयरसन पब्लिकेशन; 2018.
9. विश्व बैंक. विश्व विकास रिपोर्ट: कृषि और ग्रामीण परिवर्तन. वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक; 2021.
10. योजना आयोग. तेरहवीं पंचवर्षीय योजना: सतत और समावेशी विकास. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2014.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

Disclaimer: The views, opinions, statements, and conclusions expressed in the papers, abstracts, presentations, and other scholarly contributions included in this conference are solely those of the respective authors. The organisers and publisher shall not be held responsible for any loss, harm, damage, or consequences — direct or indirect — arising from the use, application, or interpretation of any information, data, or findings published or presented in this conference. All responsibility for the originality, authenticity, ethical compliance, and correctness of the content lies entirely with the respective authors.

© 2026 डॉ. गीता कुकावा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/